## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. 8/41//

Jabalpur, dated 2003/2024

Copy of the notification of the Government of M.P. F.No. 1327/21-B(1)/2024; Bhopal dated 19.03.2024, issued in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act; 2015, is forwarded to;

- 1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
- 2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
- 3. The Principal District and Sessions Judges; All in the State for information and necessary action;
- 4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
- 7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;

9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

(SANTOSH PRASAD SHUKLA)
REGISTRAR District Establishment

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक १९/03 /2024

फा0 क्र0 1327 /21-ब(एक) /2024- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311/19, दिनांक 05.04. 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

## सारणी

क्रं.	स्थान	न्यायिक अधिकारी का नाम (सिविल) न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"4	ग्वालियर	श्री मोहित परसाई, चौदहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर ॥"।"

#### NOTIFICATION

F.No. 1327/XXI-B(1) /2024- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311 /2019 dated 05<sup>th</sup> April,2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part-I, dated 17<sup>th</sup>, May, 2019, namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said notification, in the table, for Serial Number 4 for (Civil Judge Level) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### **TABLE**

S. No	PLACE	NAME OF THE JUDICIAL OFFICERS (CIVIL JUDGE LEVEL)
(1)	(2)	(3)
"4	Gwalior	Shri Mohit Persai, XIV <sup>th</sup> Civil Judge, Senior Division, Gwalior.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( उमेश पाण्डव ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 1327 /21-ब(एक) /2024,

भोपाल, दिनांक १९/ 03/2024

## प्रतिलिपि:-

- 1. रिजस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/2396/II-4-1/2010, दिनांक 28.02.2024 के संदर्भ में,
  - 2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
  - 3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म०प्र०), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
  - 4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
  - 5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

् (राघवेन्द्र भारद्वांज) अतिरिक्त सचिव

🖫 मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग